दैनिक
उत्तराखण्ड प्रहरी

वर्ष 15 /अंक 65 / पृष्ठ 8
हरिद्वार, गुरुवार, 0 4 मई 2023
uttarakhandprahari19@gmail.com / e-paper: uttarakhandprahari.com
उत्तराखण्ड का सबसे विश्वसनीय मीडिया पार्टनर
RNI No. : - UTTHIN/2009/27592

सुरेन्द्र सिह की तहरीर पर मुकदमा हुआ दर्ज, मंत्री का नाम ...

क्यों डूब रहे हैं अमरीकी बैंक

मूल्य- 2 रु.

विदेश में रोजगार के इच्छुक युवाओं का सपना साकार करेगी धामी सरकार

मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना को राज्य कैबिनेट ने दी मंजूरी

सुमित तिवारी / उत्तराखंड प्रहरी ब्यूरो

देहरादून। आप विदेश में रोजगार के अवसर तलाश रहे हैं और कोई रास्ता बनता नहीं दिख रहा तो चिंता की कोई बात नहीं। राज्य की धामी सरकार ने युवाओं के इस सपने को पूरा करने के लिए ''मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना'' शुरू करने का निर्णय लिया है। आज राज्य मंत्रिमंडल ने इस पर अपनी मुहर भी लगा दी है। योजना की खास बात यह है कि विदेश में रोजगार के इच्छुक युवाओं को उस लिहाज से तराशने का काम भी राज्य सरकार करेगी। इसके अतिरिक्त चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के टिकट, वीजा आदि से संबंधित प्रक्रियाओं में भी सरकार मदद करेगी। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना को आज मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया जिसे कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। बताया गया कि विदेश में रोजगार के इच्छुक युवाओं से सम्बन्धित डाटाबेस तैयार करने के लिए 'अपुणी सरकार पोर्टल' पर एप्लीकेशन विकसित की जा चुकी है। इसके अलावा विदेश रोजगार के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किये जा रहें हैं तथा अब तक इसी कड़ी में कई संस्थाओं के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हो चकें हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को विदेश में उपलब्ध रोजगार से राज्य के युवाओं को जोड़े जाने के लिए प्रदेश में कार्य करने के इच्छुक हैं।इन संस्थाओं से विचार-विमर्श के बाद प्रथम चरण में नर्सिंग और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्रों में राज्य के युवाओं हेतु उपलब्ध विदेश में रोजगार के अवसरों से जोड़े जाने हेतु कार्य किये जाने पर सहमति बनी है। इसके लिए विदेश रोजगार हेतु युवाओं को डोमेन क्षेत्र में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण के साथ-साथ सम्बन्धित देश की भाषा, संस्कृति एवं कार्य नियमों आदि के बारे में प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थियों के टिकट वीजा आदि से सम्बन्धित प्रक्रियाओं में भी सहयोग प्रस्तावित है।

नर्सिंग कॉलेज के प्रधानाचार्य संग हो चुकी है बैठक

नर्सिंग के क्षेत्र में विदेश में उपलब्ध रोजगार के अवसर की जानकारी देने के लिए समस्त नर्सिंग कॉलेजों के प्रधानाचार्यों के साथ वर्कशॉप की जा चुकी है तथा उनके द्वारा इस समबन्ध में पूर्ण सहयोग प्रदान किये जाने का आश्वासन भी दिया गया है। इसके अलावा नर्सिंग एवं हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्रों प्रशिक्षण प्रदान कर रहीं विभिन्न संस्थाओं से इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श एवं युवाओं के साथ वर्कशॉप की जा चुकी है।

9 मई को होगी वर्कशॉप

आगामी 9 मई को विभिन्न नर्सिंग कॉलेजों से एएनएम एवं जीएनएम उतीर्ण युवाओं हेतु जापान में एल्डरली केअर में उपलब्ध रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान किये जाने के लिए वर्कशॉप भी रखी गयी है तथा उक्त वर्कशॉप में ही इच्छुक युवाओं का स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जायेगा तथा चयनित युवाओं का प्रशिक्षण आरम्भ किया जायेगा ।यह प्रशिक्षण स्किल हब सहसपुर में होना प्रस्तावित है।

आबकारी मामला: सांसद राघव चड्ढा , तो बोले-मेरी छवि बिगाड़ने की कोशिश

नई दिल्ली। आबकारी नीति में कथित घोटाले मामले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सासंद राघव चड्ढा के नाम का ज़िक्र किया है. हालांकि, उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है. इस मामले पर राघव चड्ढा ने कहा कि उनके ऊपर किसी प्रकार का आरोप नहीं है. उन्होंने कहा, ''ईडी द्वारा दायर की गई किसी भी शिकायत में मुझे आरोपी या संदिग्ध के रूप में नामित नहीं किया गया है. इन शिकायतों में मुझ पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है.'' खबर है कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पीए ने राघव चड्ढा का नाम लिया था। इस पर 'आप' के राज्यसभा सांसद ने कहा, ''ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायत में मेरा नाम किसी बैठक में उपस्थित व्यक्ति के रूप में उल्लिखित है, हालांकि इस तरह के आरोप लगाने का आधार स्पष्ट नहीं है.'' अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है।

'सर्वशक्तिमान' प्रधानमंत्री को कर्नाटक में 'भाजपा सरकार की लूट' क्यों नहीं दिखी: कांग्रेस

गुलबर्गा (कर्नाटक),(भाषा)। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने कर्नाटक की 'भारतीय जनता पार्टी सरकार के भ्रष्टाचार' को लेकर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर तीखा प्रहार किया और कटाक्ष करते हुए कहा कि 'सर्वशक्तिमान, सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ और सर्वज्ञानी' प्रधानमंत्री को कर्नाटक में '40 प्रतिशत कमीशन सरकार की लूट' नजर क्यों नहीं आई। उन्होंने विजयपुरा और बीदर जिलों में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए लोगों का आह्वान किया कि वो भाजपा को सबक सिखाएं और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दें ताकि उनके हित में काम हो सके।

बाद में प्रियंका गांधी ने गुलबर्गा में एक रोडशो भी किया जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कांग्रेस महासचिव ने यह सवाल भी किया कि 'विकास पुरूष' (मोदी) अब भी ऐसा क्यों कहते हैं कि कर्नाटक का विकास उनका सपना है? विजयनगर के इंडी इलाके की सभा में प्रियंका गांधी ने कहा, ''मुझे ताज्जुब हुआ कि जिन्हें दुनिया, उनके लोग सर्वशक्तिमान, सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ और विकास पुरूष कह रहे हैं वह यहां आकर कहते हैं कि मेरा सपना था कि कर्नाटक का विकास हो।

शाह ने नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों को वितरित किए नियुक्ति पत्र

नयी दिल्ली (वार्ता)। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को यहां नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद् के 4400 कर्मियों के नियमितीकरण के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, विदेश राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी और केन्द्रीय गृह सचिव सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। शाह ने कहा कि सरकार में शीर्ष नेतृत्व ने फैसले लेने की अपनी क्षमता के कारण कई क्षेत्रों में अनिश्चितताओं का अंत करने में सफलता प्राप्त की है और उसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण आज का यह कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि

देश का हर बुजुर्ग, बच्चा और युवा यही कहता है , 'मोदी है तो मुमकिन' है। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वयं हर मंत्रालय में नौकरी की शर्तों और भर्ती के नियमों में समयानुकूल बदलावों पर बहुत जोर दिया है ।केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इस निर्णय के कारण समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को गौरव और सम्मान और सम्मान मिला है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में आज जब भारत जी-20 की अध्यक्षता कर रहा है, उस वक्त आपका बढ़ा हुआ उत्साह दिल्ली को संवारने में बहुत काम आएगा। शाह ने कहां की नगर पालिका परिषद का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां देश की नीतियों का निर्धारण होता है।

शरद पवार ने किया NCP के अध्यक्ष पद छोड़ने का एलान

नई दिल्ली। दिग्गज राजनेता शरद पवार ने मंगलवार को घोषणा की कि वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख के पद को छोड़ रहे हैं. पवार ने कहा, "मैं जनता हूं कि मुझे कहां और कब रुकना है इसलिए मैं एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं." उन्होंने कहा कि, "मैंने सिर्फ पार्टी के पद से इस्तीफा दिया है पार्टी के बाकी का काम करता रहूंगा. मैं पार्टी के नेताओं के साथ हमेशा खड़ा हूं." शरद पवार के पार्टी पद से इस्तीफा दिए जाने के एलान के बाद से ही अचानक पार्टी के नेता और समर्थक भावुक हो गए और उन्होंने पवार से उनके विचार पर एक बार फिर से सोचने की गुजारिश की।

जरा हट के...

आवश्यक सूचना

'उत्तराखंड प्रहरी' के सभी पाठकों को सूचित किया जाता है कि आप अपने प्रिय अखबार 'उत्तराखंड प्रहरी' महाभियान में शामिल हो सकते हैं। आप अपने द्वारा लिखी गई कोई भी संरचना, कविता, कहानी, लेख या कार्यक्रम हमसे साझा कर सकते हैं। अच्छे लेख व कहानी को 'उत्तराखंड प्रहरी' में उचित स्थान दिया जाएगा। आप अपने प्रियजनों को जन्मदिन, सालगिरह या अन्य शुभ अवसरों पर बधाई संदेश भी दे सकते हैं।

आप हमें ईमेल
uttarakhandprahari19@gmail.com या whatsup no 8077771906 पर भी भेज सकते हैं।

संपादकीय

पुराने एजेंडे का घोषणापत्र

जनसंघ के दौर से तीन बुनियादी मुद्दे रहे हैं-अयोध्या में राम मंदिर, अनुच्छेद 370 को समाप्त करना और समान नागरिक संहिता। पार्टी का रूपांतरण भाजपा के तौर पर हुआ, तो यह पुराना एजेंडा बरकरार रखा गया। अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर आकार ले रहा है और जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 संसद के जरिए समाप्त किया जा चुका है। हालांकि यह मामला अभी सर्वोच्च अदालत में विचाराधीन है। अब भाजपा समान नागरिक संहिता को लागू करने पर आमादा है। यानी एक देश, एक कानून। कर्नाटक के चुनाव घोषणा पत्र में भी इसे रखा गया है। भाजपा ने उत्तराखंड, हिमाचल, उप्र, मप्र, गुजरात और असम आदि राज्यों में समान नागरिक संहिता के संदर्भ में या तो कमेटी का गठन किया गया है अथवा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। हिमाचल को छोड़ कर शेष राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने भी इस मुद्दे पर आश्वासन दिया है, तो महाराष्ट्र के एक भाजपा विधायक ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को, इसी संदर्भ में मांग करते हुए, पत्र लिखा है। दरअसल जब-जब चुनाव आते हैं, तो समान नागरिक संहिता का आश्वासन गरमाने लगता है।

अलबत्ता केंद्र में बीते 9 साल से भाजपा की मोदी सरकार कार्यरत है, लेकिन न तो विधि आयोग से यह मुद्दा पारित कराया गया, न आयोग की कोई अनुशंसा है और न ही राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है। वैसे यह मामला समवर्ती सूची में है। केंद्र और राज्य सरकारें अपने स्तर पर इसे लागू कर सकती हैं। सर्वोच्च अदालत भी इसे लागू करने की बात कह चुकी है। अब एक टीवी साक्षात्कार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा है कि हम बिल ला सकते हैं। बहरहाल उसके लिए संसद सत्र का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव तक समान नागरिक संहिता को गरमाए रखेगी। फिर चुनाव के बाद देखा जाएगा। कर्नाटक में समान नागरिक संहिता के साथ-साथ भाजपा ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की भी घोषणा की है। आश्चर्य है कि दक्षिण के किसी भी राज्य का अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर नहीं है, तो अवैध घुसपैठियों या प्रवासियों की पहचान के लिए कर्नाटक में एनआरसी लागू करने की घोषणा क्यों की गई है? यह बेहद विवादास्पद और मुसलमानों में भय पैदा करने वाली घोषणा है। असम के स्तर पर इसका प्रयोग किया जा चुका है। उसमें कई विरोधाभास और विसंगतियां सामने आई थीं। मामला सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा। समान नागरिक संहिता और एनआरसी के जरिए और अन्य घोषणाओं के तहत भाजपा ने कर्नाटक में भी 'हिन्दुत्व' पर फोकस रखा है। पार्टी ने 2500 करोड़ रुपए से 5 सर्किट बनाने का वायदा किया है-परशुराम के 3 सर्किट, गंगापुरा सर्किट और कावेरी सर्किट। इनके अलावा, गोवध प्रतिबंध कानून और जबरन धर्मांतरण कानून को अधिक सख्त बनाने की भी घोषणा की गई है। भाजपा ने 'मंदिर अर्थव्यवस्था' की सोच के तहत मंदिरवादी लोगों की अपेक्षाओं और मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। मंदिर परिसरों में या उनके बाहर मुसलमानों के कारोबार और त्योहारों के दौरान दुकानें स्थापित करने पर पाबंदी लगाई जाए, कर्नाटक के मंदिरवादी हिन्दुओं की यह मांग तो पूरी तरह 'असंवैधानिक' है। अभी हमने मुफ्तखोरी की रेवड़ियों पर टिप्पणी नहीं की है, क्योंकि उस 'हम्माम' में सभी दल नंगे हैं। भाजपा, कांग्रेस और जद-एस सभी ने चुनाव में रेवड़ियां बांटने की घोषणाएं की हैं। बेशक वे जन-कल्याण का दावा करें।

क्यों डूब रहे हैं अमरीकी बैंक

डा. वरिदर भाटिया

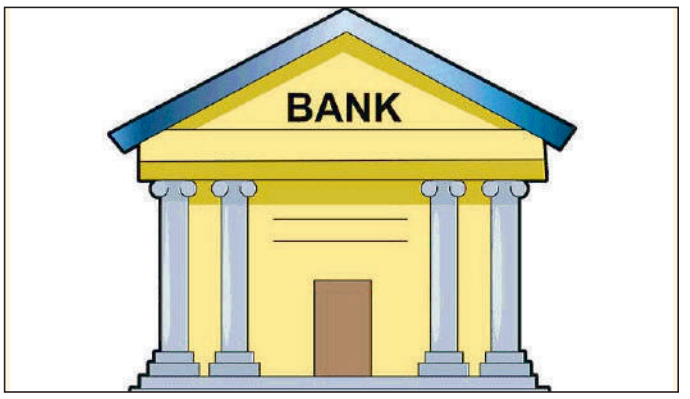

अमरीका के बैंकिंग सेक्टर में मुसीबतों का दखल जारी है। यहां एक के बाद एक नामी बैंक खलास होते जा रहे हैं। हाल ही में अमरीका में एक और नामचीन प्राइवेट बैंक डूब गया। अमीर लोगों की जरूरतों को पूरा करने वाला अमरीका का मशहूर बैंक फस्ट रिपब्लिक बैंक भी बिक गया है। इस बैंक को जेपी मॉर्गन ग्रुप ने खरीद लिया है। बीते कुछ महीनों में अमरीका में तीन बड़े बैंक डूबे हैं। इन बैंकों के डूबने से दुनिया भर में हलचल मची है। ग्लोबल अर्थजगत में भी चिंता की लहर है। अमरीकी आर्थिक संकट का असर पूरी दुनिया पर पडने की आशंका जताई जा रही है। भारत का बैंकिंग सेक्टर इसको हलके से नहीं ले सकता है। अमरीका के बैंकिंग इतिहास में दूसरी बार बैंकों में इस तरह की स्थिति सामने आई है। इससे पहले साल 2008 में अमरीका ने सबसे बड़ा बैंकिंग सेक्टर का बुरा हाल देखा था। उस समय बैंकिंग फर्म लेहमन ब्रदर्स ने खुद को डिफॉल्टर घोषित कर दिया था, जिसके बाद अमरीका के साथ पूरी दुनिया में मंदी छा गई थी।

इस दौरान अमरीका की इकोनॉमी की कमर टूट गई थी। यह जानना जरूरी है कि आखिर अमरीका में ऐसा क्या हुआ कि यहां एक के बाद एक बैंक खाक होते जा रहे हैं। आईये इस आर्थिक मुद्दे की गहराई में जाएं। सबसे पहले नकदी संकट से जूझ रहा अमरीका का फस्ट रिपब्लिक बैंक बंद हो गया है। इस बैंक को खरीदने वाले जेपी मॉर्गन ग्रुप के अनुसार उसने एफआरबी के एसेट्स का बड़ा हिस्सा खरीद लिया है। इसके पास बैंक की कुछ देनदारियां भी आ गई हैं। बंद हुए अमरीका के फस्ट रिपब्लिक बैंक की शाखाएं 8 राज्यों में फैली थी। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार फस्ट रिपब्लिक बैंक की अमरीका के 8 राज्यों में 84 ब्रांचें थी। जेपी मॉर्गन ग्रुप द्वारा खरीदे जाने के बाद अब इन सभी राज्यों में फस्ट रिपब्लिक बैंक के बदले जेपी मॉर्गन चेस बैंक की शाखाएं दोबारा खुलेंगी। फस्ट रिपब्लिक बैंक अमरीका के अमीर लोगों की जरूरतों को पूरा करने वाला फेमस प्राइवेट बैंक था। यह वेंचर कैपिटल फम्र्स पर फोकस्ड सिलिकॉन वैली बैंक की तरह ही था, जो मार्च में गिर गया था। अमरीका में मार्च 2023 से अभी तक तीन बैंक डूबे हैं। फस्ट रिपब्लिक बैंक से पहले मार्च में सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक डूब गए थे। इन तीनों बैंकों के डूबने के पीछे नकदी संकट को कारण बताया जा रहा है। फस्ट रिपब्लिक बैंक को बीते वर्षों में कई बार बेचा और खरीदा गया। साल 2007 में मेरिल लिंच एंड कंपनी ने 1.8 अरब डॉलर में फस्ट रिपब्लिक बैंक को खरीदा था। इसके बाद 2009 में इसे बैंक ऑफ अमेरिका ने खरीदा। इसके बाद साल 2010 में इन्वेस्टमेंट फर्म जनरल अटलांटिक और कॉलोनी कैपिटल ने इसे 1.86 अरब डॉलर में खरीदा। इसके बाद इसे पब्लिक कर दिया गया था। अमरीकी बैंकिंग सेक्टर में आए संकट को समझने के लिए सिलिकॉन वैली बैंक का उदाहरण सटीक है। इस संकट के कारण तबाह होने वाला सिलिकॉन वैली बैंक अमरीका का पहला बैंक था। बैंकिंग सेक्टर को समझने वाले एक्सपर्ट बताते हैं कि सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने की वजह बैंक के कुछ गलत फैसले थे। दरअसल सिलिकॉन वैली बैंक उन स्टार्टअप को भी कर्ज देता था जिन्हें कोई दूसरा बैंक हाथ तक नहीं लगाता था। 2021 में शेयर बाजारों में तगड़ा बूम आया और ब्याज दरें लगभग जीरो हो गईं। शेयर बाजार में आए बूम के बाद टेक स्टार्टअप्स के पास बहुत सारा पैसा आया, जिसे कई स्टार्टअप ने सिलिकॉन वैली बैंक में जमा कर दिया। बैंक ने भी उन पैसों को लंबी अवधि के बॉन्ड में निवेश किया। पिछले साल जब ब्याज दरें बढ़ीं तो बॉन्ड्स अपनी वैल्यू गंवाने लगे जिसके बाद टेक स्टार्टअप्स अपने पैसे निकालने लगे। इससे बैंक को अपने बॉन्ड्स को नुकसान में बेचना पड़ा। नुकसान बढने लगा तो कंपनी के शेयर की कीमत गिरने लगी। इस सिलसिले के कुछ ही दिनों बाद सिलिकॉन वैली बैंक दिवालिया हो गया। सिलिकॉन वैली बैंक का बंद होना अमरीकी इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा दिवाला है। इससे पहले 2008 में वॉशिंगटन म्यूचुअल को अमरीका का पहला सबसे बड़ा बैंक दिवाला माना जाता है। आगे की कहानी जानें तो सिलिकॉन वैली बैंक के कुछ ही दिन बाद न्यूयॉर्क के सिग्नेचर बैंक की हालत खराब होने लगी। सिग्नेचर एफटीएक्स बैंक क्रिप्टो एक्सचेंज के पतन के साथ चर्चा में आया था। एफटीएक्स के सिग्नेचर बैंक में खाते थे। साल 2018 में ही ये बैंक क्रिप्टो असेट्स के डिपोजिट के बिजनेस में उतरा था। बैंक के लिए यही फैसला डूबाने वाला साबित हुआ।

उत्तराखंड प्रहरी

कविता

अंदाज-ए-ज़िंदगी....

जिन्दगी अपनी हम कुछ इस अंदाज में जीते हैं।
बुराईयों से कर किनारा,ग्रहण अच्छाइयों को कर लेते है।
आदर सम्मान बड़ो को,और प्यार बच्चों में बांट देते है।
बांटकर खुशियाँ दूसरों को गम खुद पी लेते हैं।
हो जाए गर भूल कोई तो क्षमा मांग लेते है।
फर्ज इंसानियत का भी हम कुछ यूं निभा देते हैं।
पुकारे जब कोई असहाय मदद को,तो सहारा दे देते हैं।
भूखे को खाना और प्यासे को पानी पिला देते हैं।

सचिन बेदी अधिवक्ता, हरिद्वार

युद्ध का किसी को लाभ नहीं होता

प्रो. मनोज डोगरा

युद्ध किसी भी देश के लिए लाभदायक सिद्ध नहीं होता है, बल्कि उससे मानवता को हानि और क्षति होती है। इसलिए युद्ध न केवल मृत्यु और विनाश का कारण बनते हैं बल्कि स्थायी शारीरिक और मानसिक चोट भी पहुंचाते हैं, जो अंत तक उन लोगों को परेशान करती रहेगी जो उनसे प्रभावित होते हैं। पृथ्वी पर जीवन अनमोल और अद्वितीय है। तार्किक रूप से, हम अपनी सभ्यता की प्रगति के ऐसे चरण में हैं कि हमें युद्धों के निहितार्थों को जानना चाहिए और उन्हें होने ही नहीं देना चाहिए। युद्धों में कोई वास्तविक विजेता नहीं होता है क्योंकि इसमें शामिल सभी पक्षों को परिणाम भुगतना पड़ता है जिसमें अक्सर दोनों पक्षों के हताहतों की संख्या अधिक होती है। जब भी युद्ध होता है, दोनों देशों को मानवीय मूल्यों से हाथ धोना पड़ता है। उन देशों की तो क्षति होती ही है, इसका असर दूसरे देशों पर भी पड़ता है, चाहे वह आर्थिक तौर पर हो, राजनीतिक, सामाजिक या नैतिक तौर पर, युद्धों से होने वाली क्षति की कभी भी भरपाई नहीं हो पाती। रूस के द्वारा यूक्रेन के खिलाफ छेड़ा गया युद्ध अभी तक जारी है और फिलहाल इसका कोई परिणाम नहीं दिख रहा, परंतु एक बात निश्चित है कि इसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ रहा है।

युद्ध चाहे कोई भी हो कौन सा भी हो लेकिन वह कभी भी किसी भी देश की लोकतांत्रिक, राजनीति और अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं होता। एक युद्ध जिन देशों के बीच में छिड़ता है केवल उनकी ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की शांति भंग करता है। इसका उदाहरण हमें यूक्रेन तथा रूस के युद्ध से मिल रहा है। यूएस और यूरोपीय अधिकारियों के अनुमान के अनुसार, यूक्रेन में युद्ध में लगभग 200000 रूसी सैनिक मारे गए या घायल हुए हैं। यह संख्या बढने की संभावना है क्योंकि क्रेमलिन आने वाले हफ्तों में एक नए हमले की तैयारी कर रहा है। युद्ध के दौरान राजधानी में, लगभग 400 आवासीय इमारतें नष्ट और क्षतिग्रस्त हो गईं जिनमें से अधिकांश बहु-अपार्टमेंट इमारतें थीं, जिनकी कीमत एक बिलियन डॉलर थी। शत्रुता के परिणामस्वरूप, क्षतिग्रस्त और नष्ट बुनियादी ढांचे की वस्तुओं की संख्या में वृद्धि जारी है। सरकार या शासक के अपने मतलब के लिए होने वाले युद्ध से आम वर्ग की जनता को हावी नुकसान होता है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पश्चिम के खिलाफ न्यायोचित युद्ध की कथा को आगे बढ़ा रहे हैं और असहमति की आवाजों को कुचल रहे हैं, जबकि उनके देश की अर्थव्यवस्था को प्रतिबंधों का दंश झेलना पड़ रहा है। हालांकि उनका प्रभाव उम्मीद से कहीं अधिक बारीक रहा है, आम जनता कभी भी युद्ध नहीं चाहती बल्कि यह तो उसे झेलना पड़ता है, वो तो अपने शासक के निजी कारणों की वजह से इसमें पिस जाती है। केवल एक व्यक्ति की वजह से जो कि स्वयं युद्ध लड़ता भी नहीं है उसकी वजह से लाखों बेकसूर लोगों की जान चली जाती है।

वैधानिक सूचना

उत्तराखंड प्रहरी के संपादन में हम प्रयासरत है कि हमारी ओर से खबर में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि न हो। हमारी कोशिश है कि अखबार में छपी किसी खबर, रिपोर्ट, फीचर या लेख से व्यक्ति विशेष, संगठन या समुदाय की भावना को ठेस न पहुंचे। **उत्तराखंड प्रहरी** में प्रकाशित लेख, विश्लेषण और साभार, ली गई सामग्री के विचार संबंधित लेखकों और रचनाकारों के निजी विचार हैं, न कि अखबार के। अतः सभी पाठकों से आग्रह है कि वे किसी सूचना, समाचार, विज्ञापनों आदि के आधार पर कोई फैसला करने से पहले तथ्यों की स्वयं पुष्टि कर लें। उसके लिए किसी भी प्रकार से लेखक, संपादक, प्रकाशक, प्रिंटर या विक्रेता को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। तथा किसी भी कारोबारी और निज निर्णय के लिए **उत्तराखंड प्रहरी** जिम्मेवार नहीं होगा।

सुरेन्द्र सिह की तहरीर पर मुकदमा हुआ दर्ज, मंत्री का नाम भूली पुलिस ?

उत्तराखंड प्रहरी ब्यूरो

देहरादून। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और युवक के बीच मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद मामला गरमा गया है। सीएम धामी ने डीजीपी को पूरे मामले जांच के आदेश दिए थे। जिसके बाद आज मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पीआरओ और गनर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं, देर रात युवक पर भी मामला दर्ज हो चुका है। ऋषिकेश कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक खुशीराम पांडे ने बताया कि सुरेंद्र नेगी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ बलवा मारपीट व गाली गलौज की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

प्रदेश में राजनीतिक माहौल मंगलवार को उस समय बहुत गरमा गया जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और उनका गनर बीच सड़क पर एक युवक की पिटाई करते दिखे। वायरल वीडियो में कैबिनेट मंत्री सड़क किनारे अपने वाहन के पास खड़े होकर शिवाजी नगर निवासी युवक सुरेंद्र सिंह नेगी से बात कर रहे हैं। बातचीत अचानक हाथापाई में बदल गई। वीडियो में मंत्री सुरेंद्र पर थप्पड़ मारते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद उनका गनर भी हाथापाई करने के बाद लातें मारते हुए दिख रहा है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हम जाम में फंसे थे। उसी समय बाइकसवार दो युवक गाड़ी के बगल आकर गाली देने लगे। हमने समझाया तो युवक ने कॉलर पकड़कर हाथापाई कर दी। इस बीच हमारा कुर्ता फट गया। सुरक्षाकर्मी ने रोका तो उनकी वर्दी फाड़ दी गई। मंत्री के थप्पड़ खाने वाला युवक सुरेंद्र नेगी नगर निगम ऋषिकेश के शिवाजी नगर क्षेत्र के निवासी हैं। वे काफी समय से सामाजिक और जनहित के आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं। वे शिवाजीनगर क्षेत्र से ही निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नगर निगम पार्षद का चुनाव भी लड़ चुके हैं। वह अपने घर के पास परचून की दुकान चलाते हैं।

कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला ने कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली में पहुंच कर मंत्री के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की तानाशाही चरम पर है। वह जुबानी जंग के बाद हाथापाई पर उतारू हो गए हैं। कैबिनेट मंत्री और उनके गनर ने शिवाजी नगर निवासी युवक सुरेंद्र नेगी को बेरहमी से पीटा है। यदि युवक की गलती थी तब भी मंत्री को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। जयेंद्र ने मांग की कि कैबिनेट मंत्री और उनके गनर पर मुकदमा दर्ज किया जाए अन्यथा पीड़ित युवक को साथ लेकर कांग्रेस आंदोलन करेगी।

ग्राम में समय अनुसार होंगे कार्य और समाधानः हरेंद्र चौधरी

हरिद्वार। आज क्षेत्रिय ग्राम प्रधान जमालपुर का जन्म दिवस है जन्म दिवस पर प्रधान हरेंद्र चौधरी ने कहा के क्षेत्र मे कुछ कार्य हो चुके हैं और कुछ अभी बाकी हैं समय अनुसार बकाया कार्य को किया जाएगा वही प्रधान हरेंद्र चौधरी का कहना है समस्या और क्षेत्रीय दिक्कत पर पूरी नजर बनी हुई है और कार्य अनुसार मेरे कई कार्य अधूरे हैं जनता हित के लिए हमेशा तत्पर रहते हुए आगे के कार्य की योजना बनाई गई है। सभी क्षेत्रीय भाई बहनों से अपील है कृप्या क्षेत्रीय कार्य के लिए मुझे सीधा संपर्क करें मै आपका सेवक हूं जो कार्य मेरी नजर से दूर है उसके लिए मुझे ज्ञात कराए तत्काल प्रभाव से उनको किया जाएगा पिछले कुछ दिनों पहले गर्मी को देखते हुए प्रधान द्वारा कई हैडपंप और कई वाटर कूलर की मरम्मत कराई गई है ताकि जनता को पीने के पानी की समस्या से निजात मिल सके और ऐसे कई कार्य पर नजर बनी हुई है।

सीवर हुए ओवरफ्लो, जिलाधिकारी ने मौके पर पहुंच किया निरीक्षण

संवाददाता : त्रिभुवन जोशी,(उत्तराखंड प्रहरी ब्यूरो)

पिथौरागढ़। नगरपालिका पिथौरागढ़ के अंतर्गत स्थित शिवालया लाईन कॉलोनी में सीवर के ओवरफ्लो होने सम्बन्धी शिकायतों के समाधान के दृष्टिगत जिलाधिकारी रीना जोशी ने शिवालया लाईन कॉलोनी का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने शिवालया लाईन कॉलोनी वासियों की सीवर ओवर फ्लो होने सम्बन्धी समस्याएं सुनी। जिलाधिकारी ने जल संस्थान एवं जल निगम के अधिकारियों को शिवालय कॉलोनी की सीवर ओवरफ्लो होने संबंधी समस्या के समाधान हेतु कार्य करने के निर्देश दिए। वही यह भी निर्देश दिए कि कॉलोनी वासियों के साथ बैठक कर सीवर चैम्बर चौड़ीकरण व सीवर लाईन बिछाने से संबंधित कार्यों के दौरान आने वाली दिक्कतों से भी कालोनीवासियों को अवगत करा दिया जाय। प्रभारी अधिशासी अभियंता जल संस्थान सुरेश जोशी ने बताया कि शिवालय लाइन कॉलोनी में 18 परिवारों की प्राइवेट सीवर लाइन है जो जलसंस्थान के चैम्बर से जुड़ी है। प्राईवेट सीवर लाईन के चेंबर आकार में छोटे होने के कारण चौक हो जा रहे हैं जिससे सीवर ओवरफ्लो हो रहा है। जिसके समाधान हेतु जिला योजना 2023-24 के अंतर्गत रुपए 10 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई है जिससे प्राईवेट सीवर लाईन के चैम्बर चौड़ीकरण का कार्य किया जाएगा। वही अधिशासी अभियंता पेयजल निगम आर एस धर्मशत्तू ने बताया कि नये टेंडर में शिवालिया लाइन कालोनी में सीवर लाईन संबंधी अवशेष कार्य कराये जाएंगे। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी अनुराग आर्य उपस्थित थे।

शिवालय लाइन कॉलोनी में 18 परिवारों की प्राइवेट सीवर लाइन है जो जलसंस्थान के चैम्बर से जुड़ी है। प्राईवेट सीवर लाईन के चेंबर आकार में छोटे होने के कारण चौक हो जा रहे हैं जिससे सीवर ओवरफ्लो हो रहा है।

परमार्थ निकेतन में प्लास्टिक मुक्त गंगा विषय पर बुद्धिजीवियों के सम्मेलन का हुआ आयोजन

उत्तराखंड प्रहरी ब्यूरो

ऋषिकेश। परमार्थनिकेतन में 'सेंटर फॉर ग्लोबल अफेयर्स एन्ड पब्लिक पॉलिसी' की ओर से प्लास्टिक मुक्त गंगा विषय पर बुद्धिजीवियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप पधारे हेस्को के संस्थापक पदम भूषण डॉ. अनिल प्रकाश जोशी ने कहा कि प्रकृति का असन्तुलित दोहन मानव जीवन पर भारी पड़ रहा है। इसे गम्भीरता से लेने की आवश्यकता है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के प्रान्त पर्यावरण प्रमुख पर्यावरण विद एवं सामाजिक चिंतक विनोद जुगलान ने कहा कि संकल्प सिद्धि और सामूहिक प्रयासों ही गंगाजी की निर्मलता और अविरलता सम्भव है। उन्होंने कहा कि परमार्थ में कार्यक्रम के आयोजन की सफलता तभी सम्भव है जब सभी लोग यहाँ से परमार्थ (लोक कल्याण) का संकल्प लेकर लौटें। इस अवसर पर सुपसिद्ध श्रीमद कथा वक्ता वैष्णवाचार्य पण्डित शिव स्वरूप नौटियाल ने कहा कि सनातन संस्कृति में गौ, गंगा और गीता, गायत्री और गणेश जी की स्तुति के साथ-साथ इन्हें संस्कारों में ढालने की जरूरत है। सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल के संचालन में चले प्रथम सत्र में वैदिक ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी आचार्य शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि प्रकृति हो या गंगाजी दोनों ही मातृ रूपेण हैं। इनके संरक्षण और सम्मान के बिना शिक्षा अधूरी है। जीआईजेड जर्मनी की संस्था के तकनीकी सलाहकार नितेश चंद्राकर और वेस्ट वारियर्स के सम्प्रेषण निदेशक ने संयुक्त रूप से माना कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही ऐसे अभियानों में सफलता पाई जा सकती है। 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान की ब्राण्ड अम्बेसडर डॉ. मनु शिवपुरी ने कहा कि सिर्फ सफाई करने के साथ हमे इसके मूल स्रोत पर भी पैनी करवाही करनी आवश्यक है। प्लास्टिक का मूल स्रोत से ही हमे विकल्प उपलब्ध होने चाहिए। अपनी स्वरचित संदेश जो कि गंगा घाटों पर प्रसारित किया जा रहा है के माध्यम से गंगा में प्लास्टिक और कपड़े फेंकने वालों को ऐसा न करने का जागरूकता संदेश देते हुए कहा कि पतित पावनी गंगाजी हमारी माँ है। इनके हृदय को दूषित न करें। नगर पालिका परिषद मुनिकीरेती के अध्यक्ष रोशन रतूड़ी ने कहा कि गंगा हम सबकी माँ है। गंगा स्वच्छता की जिम्मेदारी भी है।खासकर गंगा किनारे रहने वाले हर वर्ग के लोगों की जिम्मेदारी है कि हम गंगाजी को स्वच्छ रखें। नालियों और सड़कों पर कूड़ा न डालें यह बहते हुए गंगाजी में जाकर मिलता है। कार्यक्रम के संयोजक पीआईबी के संयुक्त निदेशक शान्तनु प्रताप सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में सामाजिक और निजी संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं स्थानीय हितधारकों के अलावा जनप्रतिनिधियों, सरकारी संस्थाओं के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। गंगा स्वच्छता से जुड़ी प्लास्टिक मुक्त गंगाजी की इस योजना में भारत की सबसे कम उम्र नौ वर्ष की मणिपुर निवासी जलवायु कार्यकर्ता लिसी, प्रिया सहित अभियान से जुड़ी डॉ. मानसी, बाल भार्गव, जसमीन ढींगरा, मोनिका, इंजि. अर्क शर्मा (स्टेट सचिव एआईसीपीओ उत्तराखण्ड) हेमंती सहित बड़ी संख्या में अनुसंधान कर्ता छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया। पीआईबी के संयुक्त निदेशक शान्तनु प्रताप सिंह ने बताया कि ऋषिकेश में आयोजित दो दिवसीय इस कार्यक्रम का समापन बंगलादेश के ढाका में आयोजत सम्मेलन में किया जाएगा। रिसर्च टीम गंगाजल की गुणवत्ता जाँच के लिए भिन्न-भिन्न स्थानों पर जाकर गंगाजी के जल वाटर सेम्पल एकत्रित कर यह पता लगाएंगे।

भाजपा सरकार के मंत्री के खिलाफ कांग्रेसियों में आया उबाल, भरी बारिश में फूंका वित्त मंत्री का पुतला

उत्तराखंड प्रहरी ब्यूरो

हरिद्वार । भाजपा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल द्वारा सड़क पर दिनदहाड़े की गई एक नवयुवक की पिटाई से आक्रोशित होकर जिला शहर कांग्रेस कमेटी हरिद्वार द्वारा चंद्राचार्य चौक पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल व मुख्यमंत्री धामी का पुतला फूंका गया।

पुतला फूंकने से पूर्व कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव चौधरी ने कहा कि भाजपा के नेता व मंत्री सत्ता के मद में इतने चूर हो गए हैं कि अब जनता वह निर्दोष लोगों को सड़कों पर सड़क छाप गुंडे की तरह मारपीट करते हुए दिखाई देते हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा कल ऋषिकेश में सुरेंद्र सिंह नेगी नामक व्यक्ति के साथ की गई मारपीट को सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए व कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। शहर कांग्रेस कमेटी हरिद्वार के कार्यकारी अध्यक्ष अमन गर्ग ने कहा की भाजपा के नेता बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं और इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं जिस तरीके से भाजपा के कैबिनेट मंत्री द्वारा ऋषिकेश में कल सड़क पर एक निर्दोष

के साथ मारपीट की वे इसके बाद सत्ता की धौंस जमाते हुए उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर दिया इससे पता लगता है कि प्रेमचंद अग्रवाल सत्ता के नशे में चूर हो गए हैं ऐसे व्यक्ति को कैबिनेट मिनिस्टर के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है इसलिए हम मुख्यमंत्री से मांग करते है कि प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसको जेल भेजा जाए वह मंत्री पद से तुरंत बर्खास्त किया जाए। एससीएसटी महानगर अध्यक्ष विपिन पेवल जिला महामंत्री मनीष सैनी ने संयुक्त रूप से कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी हाईकमान, सड़क छाप गुंडे प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ कार्यवाही नहीं करेंगे तब तक कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार भाजपा की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। ब्लॉक अध्यक्ष जतिन हांडा वह विकास चंद्र अमित नौटियाल द्वारा संयुक्त रूप से कहा गया की प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ तुरंत पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए इनका पहले भी विवादों से नाता रहा है नरेंद्र मोदी व धामी को एक मिसाल कायम करनी चाहिए कि जो कानून को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। पुतला दहन कार्यक्रम में मुख्य रूप से रियाजुल अली, ठाकुर रतन सिंह, शुभम जोशी दिव्यांश अग्रवाल, समर्थ अग्रवाल, अमित नौटियाल, मस्सवर सलमानी, मास्टर मुरसलीन हाजी रानी, मोहम्मद आजम, राजेंद्र जाटव, विमल साहू आदि लोग शामिल रहे।

जिलाधिकारी ने दिए निस्क्रान्त सम्पति एवं शत्रु सम्पति को कब्जामुक्त करने के निर्देश

देहरादून। जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में जिलाधिकारी शिविर कार्यालय में शत्रु सम्पत्ति के सम्बन्ध में बैठक हुई। जिलाधिकारी ने निस्क्रान्त सम्पति एवं शत्रु सम्पति को कब्जामुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा कि निस्क्रान्त एवं शत्रु सम्पत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर बैठे हुए लोगों चेतावनी दी गई कि वे आना कब्जा स्वयं हटा लें अन्यथा सम्बन्धित के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के साथ ही अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही की जाएगी।

अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने जानकारी देते हुए बताया गया कि जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में चकराता के ग्राम ठाणा में अवस्थित शत्रु सम्पति को उप जिलाधिकारी चकराता (राज्य सरकार) के अभिरक्षण में लिया गया है। इसी प्रकार मसूरी में कैमलबैक रोड दिलाराम स्टेट पर अवस्थित सम्पत्ति पर कब्जा लेने की कार्यवाही गतिमान है। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉ एस के बरनवाल, नगर मजिस्टेट कुशम चौहान, सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित है।

विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली विभाग (आर आई सएस) विदेश मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में G-20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट लेक्चर सीरीज का आयोजन

उत्तराखंड प्रहरी ब्यूरो

देहरादून। ऋषिकेश पंडित ललित मोहन शर्मा परिसर ऋषिकेश श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय एवं विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली विभाग (आर आई सएस) विदेश मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में G-20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट लेक्चर सीरीज का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता वियतनाम में भारत की पूर्व राजदूत व भूतपूर्व सचिव, विदेश मंत्रालय प्रीति सरन आई एफ एस रही। उन्होंने अपने वक्तव्य में जी-20 की अध्यक्षता के बारे में प्रकाश डाला तथा युवाओं की इसमें भागीदारी तथा अन्यजनों की भागीदारी पर बल दिया। उन्होंने कोविड, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, कनफ्लिक्ट (संघर्ष) के बारे में कहा व इसमें भारत की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने सतत विकास में भारत की निरंतर प्रगति पर बात की।

इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय कुलपति प्रो एन के जोशी ने अपने उद्बोधन में कृषि, वानिकी, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा व पर्यटन पर अपनी बात रखी व युवाओं से अपील कि वह अनुसंधान एवं नवाचार, रिसर्च पब्लिकेशन व उद्यमशीलता की ओर अग्रसर हों इससे G20 के आयोजन की सार्थकता सिद्ध होगी। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि व वक्ता दून विश्वविद्यालय के डीन स्टूडेंट वेलफेयर व मैनेजमेंट के विभागाध्यक्ष प्रो एच सी पुरोहित ने अपने व्याख्यान में अमृत काल के बारे में कहा कि भारत एक सशक्त व सुदृढ़ भारत के रूप में उभर रहा है उन्होंने गांधीवादी विचारधारा को अपनाते हुए अग्रसर होने की बात कही। उन्होंने वोकल फॉर लोकल पर बात रखी व योग नगरी ऋषिकेश के बारे में कहा विस्तृत से बताया।

उक्त कार्यक्रम के दूसरे वक्ता ऑनलाइन माध्यम से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के लाइफ साइंस के प्रोफेसर व स्पेशल मेडिसिन के डायरेक्टर प्रो. राणा प्रताप सिंह ने छात्र-छात्राओं से वैज्ञानिक स्वभाव के द्वारा परेशानियों को दूर करने के टिप्स दिए, उन्होंने आयुर्वेद से सम्बंधित वात पित्त कफ से लेकर अनुवांशिकी तक विस्तार से समझाया, उन्होंने जलवायु परिवर्तन सतत विकास व यूथ20 के बारे में छात्रों को बताया। विदेश मंत्रालय भारत सरकार की रिसर्च कंसलटेंट डॉ अंशुमन गुप्ता ने अपने वक्तव्य में विकसित देशों के द्वारा उत्सर्जित किए जाने वाले ग्रीनहाउस गैस से जलवायु परिवर्तन के बारे में प्रकाश डाला।

विश्वविद्यालय परिसर के प्राचार्य प्रोफेसर एम एस रावत ने सभी वक्ताओं व अतिथियों का विश्वविद्यालय की ओर से स्वागत किया व आर आई एस तथा विदेश मंत्रालय भारत सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया जो उन्होंने 75 विश्वविद्यालयों में से एक हमारा विश्वविद्यालय को इस कार्यक्रम के लिए चुना। उन्होंने भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए प्रस्ताव व न्योता दिया। इस कार्यक्रम के आयोजन सचिव डॉ एसके कुड़ियाल द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत व इस कार्यक्रम के उद्देश्य एवं रूपरेखा पर प्रकाश डाला गया।उन्होंने जी 20 के आलोक में 25 अप्रैल से आयोजित निबन्ध/ पोएट्री/पोस्टर प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा की करी इसी क्रम में पोएट्री में प्रथम स्थान रजत नेगी, द्वितीय स्थान करीना तृतीय स्थान हंसराय ने प्राप्त किया। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्रतिभा वर्मा द्वितीय स्थान समीक्षा उनियाल तृतीय स्थान रवीना व पोस्टर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आंचल गुप्ता द्वितीय स्थान सोनी तृतीय स्थान तन्मय कुमार ने प्राप्त किया।

सभी विजेताओं को मुख्य अतिथियों के द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम के समन्वयक प्रोफेसर गुलशन कुमार ढींगरा ने अंत में सभी अतिथियों व वक्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए विशेष रूप से आरआईएस (विकासशील देशों की अनुसंधान एवं विकास प्रणाली) व विदेश मंत्रालय भारत सरकार व प्रीति सरन का धन्यवाद ज्ञापन किया। अंत में सभी अतिथियों को विश्वविद्यालय परिसर की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इस मौके पर विश्वविद्यालय परिसर के समस्त संकाय अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष व प्राध्यापक एवं कर्मचारी व लगभग 150 छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

अडानी टोटल गैस के वित्तीय प्रदर्शन में सुधार, तिमाही लाभ 21 प्रतिशत बढ़ा

नयी दिल्ली, (वार्ता)। अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने 31 मार्च 2023 को समाप्त पिछले वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में सालाना आधार पर 20.74 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 97.91 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया। इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में कंपनी ने 81.09 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया था।

अडानी समूह और फ्रांस की टोटल एनर्जी का यह संयुक्त वाहनों को सीएनजी और घरों में पाइप्ड गैस की खुदरा बिक्री करता है। कंपनी के मंगलवार को जारी तिमाही नतीजों के अनुसार आलोच्य तिमाही (जनवरी-मार्च 2023) में परिचालन से उसका राजस्व 12.37 प्रतिशत बढ़कर 1197.31 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले इसी अवधि में 1065.48 करोड़ रुपये था। अक्टूबर-दिसंबर, 2022 की तिमाही में कंपनी का राजस्व 1185 करोड़ रुपए रहा। कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष 2022-23 के लिए प्रत्येक एक रुपये के अंकित मूल्य के प्रति शेयर पर 25 पैसे (25 प्रतिशत) की दर से लाभांश दिए जाने की सिफारिश की है।

अडानी टोटल गैस ने पूरे वित्तीय वर्ष 2022-23 में 46.06 की वृद्धि के साथ 4683.39 करोड़ रुपये का राजस्व दर्ज किया। वित्त वर्ष 2021-22 में कंपनी का राजस्व 3206.36 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी का शुद्ध लाभ 7.28 प्रतिशत बढ़कर 546.49 करोड़ रुपये हो गया। इससे पिछले वित्त वर्ष (2021-22) में उसे 509.40 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। कंपनी का कहना है कि बिक्री मूल्य में वृद्धि के साथ बिक्री की मात्रा बढ़ने से उसके परिचालन राजस्व में सुधार हुआ। पिछले वित्त वर्ष के कारोबार पर कंपनी ने बयान में कहा कि उसके सीएनजी नेटवर्क के विस्तार के चलते सीएनजी की बिक्री मात्रा के हिसाब से सालाना आधार पर 28 प्रतिशत ऊंची रही, लेकिन औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा गैस की कम खपत के कारण पीएनजी की बिक्री की मात्रा 13 प्रतिशत गिर गयी।कंपनी ने कहा है कि उसने पूरे देश में 26 स्थानों पर 104 ईवी चार्जिंग पॉइंट चालू किए गए हैं तथा वाराणसी, में पहला कम्प्रेस्ड बायो-गैस (सीबीजी) स्टेशन भी चालू किया गया है। अडानी टोटल गैस के कार्यकारी निदेशक और सीईओ सुरेश पी मंगलानी ने कहा, "एटीजीएल का प्रदर्शन मजबूत रहा है। पूरे साल उच्च गैस की कीमतों के बावजूद चौतरफा भौतिक बुनियादी ढांचे और वित्तीय- दोनों मोर्चे पर अच्छा काम हुआ। स्टील पाइपलाइन नेटवर्क का तेजी से विकास और नए क्षेत्रों में सीएनजी स्टेशनों के विस्तार से प्राकृतिक गैस के कारोबार के पारिस्थितिकी तंत्र को मदद मिली है।

अजय बंगा होंगे विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष

वाशिंगटन/ नयी दिल्ली (वार्ता)। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों ने बुधवार को अजय बंगा को इस बहुपक्षीय वित्तीय संगठन के अध्यक्ष पद के लिए चुना।

वैश्व बैंक की विज्ञप्ति के अनुसार श्री बंगा को पांच साल के लिए अध्यक्ष चुना गया है। उनका सेवा काल 02 जून से शुरू होगा। श्री बंगा को भारत सरकार ने 2016 में पद्म श्री अलंकरण से सम्मानित किया था। वह बहुत सारे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं।

भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक श्री बंगा हाल तक जनरल अटलांटिक कंपनी के उपाध्यक्ष थे। इससे पहले वे मास्टर कार्ड जैसी वैश्विक भुगतान सेवा कंपनी के अध्यक्ष एवं कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) थे, जिसके दुनियाभर में करीब 24 हजार कर्मचारी हैं। बंगा 2020 से 2022 तक इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अवैतनिक अध्यक्ष थे। वह अमेरिकी रेड क्रॉस, क्राफ्ट फूड्स और डाउ इंक जैसे संगठनों के निवेशक मंडल में भी रह चुके हैं। श्री बंगा ने द साइबर रेडिनेस इंस्टीट्यूट के सह संस्थाक हैं। इस समय वे इकोनॉमिक क्लब ऑफ न्यूयॉर्क के उपाध्यक्ष भी हैं। बंगा का इस पद पर विश्व बैंक के शेयर धारकों द्वारा 2011 में तय चयन प्रक्रिया के तहत की गयी है। इस प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन खुली योग्यता आधारित और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया जाता है और किसी भी सदस्य देश के नागरिक को इस पद के लिए उम्मीदवार के रूप में किसी कार्यकारी निदेश या गवर्नर द्वारा नामित किया जा सकता है।

बंगा विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष होंगे और अमेरिका डेविड मलपास का स्थान लेंगे।

विश्व बैंक के निदेशकों ने विधिवत जांच पड़ताल और लंबे साक्षात्कार के बाद बंगा को इस पद के लिए चुना है। विश्व बैंक समूक का अध्यक्ष पुनर्निमाण एवं विकास के अंतरराष्ट्रीय बैंक (आईबीआरडी) के कार्यकारी निदेशकों के बोर्ड का अध्यक्ष होता है। विश्व बैंक का अध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) के निदेशक मंडल का भी अध्यक्ष होता है। उसे अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी), बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (एमआईजीए) और निवेश संबंधी विवादों के समाधान के लिए बने अंतरराष्ट्रीय केंद्र (आईसीएसआईडी) की प्रशासनिक परिषद के सभापति का भी दायित्व भी संभालना होता है।

आधार से जुड़े ईमेल/मोबाइल नंबर को सत्यापित करने की अनुमति

नयी दिल्ली (वार्ता)। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने उपयोगकर्ताओं के लाभों को ध्यान में रखते हुए निवासियों को आधार के साथ जुड़े उनके मोबाइल नंबर और ईमेल आदि को सत्यापित करने की अनुमति दी है। यूआईडीएआई के संज्ञान में आया था कि कुछ मामलों में निवासियों को इसके बारे में पता नहीं था/निश्चित नहीं था कि उनका कौन सा मोबाइल उनके आधार से जुड़ा हुआ है। इसलिए, निवासियों को चिंता थी कि आधार ओटीपी किसी दूसरे मोबाइल नंबर पर तो नहीं जा रहा है। अब , इस सुविधा के साथ निवासी इन्हें बहुत सरलता के साथ देख सकते हैं। इस सुविधा का लाभ आधिकारिक वेबसाइट पर या एमआधार ऐप के माध्यम से ' वेरिफाई ईमेल/मोबाइल नंबर 'फीचर के तहत उठाया जा सकता है। इसे निवासियों के लिए यह सत्यापित करने के लिए डेवलप किया गया है कि उनका ईमेल/मोबाइल नंबर संबंधित आधार के साथ जुड़ा हुआ है।

रुपया चार पैसे फिसला

मुंबई(वार्ता) अमेरिकी फेड रिजर्व के ब्याज दर में एक बार फिर बढ़ोतरी करने की उम्मीद में दुनिया की प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर के मजबूत होने से आज अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया चार पैसे की गिरावट लेकर 81.86 रुपये प्रति डॉलर रह गया। इसके पिछले कारोबारी दिवस रुपया 81.82 रुपये प्रति डॉलर रहा था। शुरुआती कारोबार में रुपया सात पैसे की बढ़त लेकर 81.75 रुपये प्रति डॉलर पर खुला और सत्र के दौरान हुई बिकवाली की बदौलत 81.73 रुपये प्रति डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। लिवाली के दबाव में यह 81.95 रुपये प्रति डॉलर के निचले स्तर पर भी रहा। अंत में पिछले सत्र के 81.82 रुपये प्रति डॉलर की तुलना में चार पैसे की गिरावट लेकर 81.86 रुपये प्रति डॉलर रह गया।

टाटा स्टील का समेकित शुद्ध लाभ चौथी तिमाही में घट कर 1,566 करोड़ रुपये

नयी दिल्ली, (वार्ता)। टाटा स्टील ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में समेकित रूप से 1,566 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया जो एक साल पहले इसी अवधि से 84 प्रतिशत कम है। एक साल पहले की अवधि में कंपनी का समेकित शुद्ध लाभ 9,835 करोड़ रुपये था। टाटा स्टील का चौथी तिमाही का राजस्व 62,962 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की इसी अवधि के 69,323 करोड़ रुपये से 9.2 प्रतिशत कम है। कंपनी का ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले का लाभ (एबिडटा) आलोच्य तिमाही में सालाना आधार पर 52 प्रतिशत घटकर 7,225 करोड़ रुपये रहा और परिचालन मार्जिन एक साल पहले की अवधि के 21.7 प्रतिशत से घटकर 11.5 प्रतिशत रही। इस दौरान कंपनी की स्टील बिक्री इससे पिछली तिमाही से नौ प्रतिशत बढ़ कर 51.5 लाख टन रही। कंपनी के मंगलवार को जारी तिमाही वित्तीय परिणामों के पर टाटा स्टील के मुख्य कार्यपालक अधिकारी टी वी नरेंद्रन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक ने कहा कि भारत में उनके कच्चे इस्पात का उत्पादन पूरे वित्तीय वर्ष में लगभग 1.99 करोड़ टन रहा जो कंपनी समूह के कुल समेकित उत्पादन का 65 प्रतिशत है।

एमएसएमई के लिए विवाद से विश्वास योजना शुरू

नयी दिल्ली (वार्ता) सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को कोविड अवधि के लिए राहत प्रदान करने के लिए "विवाद से विश्वास - प्रथम एमएसएमई को राहत" योजना का शुभारम्भ किया है।

इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में की थी। उन्होंने केंद्रीय बजट के अनुच्छेद 66 में कहा था ""एमएसएमई द्वारा कोविड अवधि के दौरान अनुबंधों को निष्पादित करने में विफलता के मामलों में, बोली या प्रदर्शन सुरक्षा से संबंधित जब्त की गई राशि का 95 प्रतिशत सरकार और सरकारी उपक्रमों द्वारा उन्हें वापस कर दिया जाएगा। इससे एमएसएमई को राहत मिलेगी।" वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने फरवरी में एक आदेश जारी कर योजना के व्यापक ढांचे का संकेत दिया था। इस संबंध में अंतिम निर्देश कोविड से प्रभावित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को हुए नुकसान को कवर करने के लिए विस्तार और रिफंड की सीमा में छूट 11 अप्रैल 2023 को जारी की गई थी। यह योजना 17 अप्रैल 2023 से शुरू की गई थी और दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 है। कोविड-19 महामारी का अर्थव्यवस्था पर गहन असर पड़ा है। विशेष रूप से एमएसएमई पर इस महामारी का विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राहत एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने और उसे जारी रखने में सरकार के प्रयासों का प्रतिरूप है। योजना के तहत, मंत्रालयों को प्रदर्शन सुरक्षा, बोली सुरक्षा और कोविड-19 महामारी के दौरान ज़ब्त/कटौती किए गए नुकसान की भरपाई करने के लिए कहा गया है। मंत्रालय ने इस योजना के माध्यम से कोविड-19 अवधि के दौरान प्रभावित एमएसएमई को अतिरिक्त लाभ देने का निर्णय लिया।

कहीं बेमौसमी बरसात में न धुल जाए आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग के होने वाले मुकाबलों पर मौसम का संकट

धर्मशाला। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 17 व 19 मई को खेले जाने वाले आईपीएल क्रिकेट मैचों पर बारिश का संकट मंडराने लगा है। मई महीने में बरसात की तरह हो रही बारिश से सभी लोग हैरत में हैं और आईपीएल के दौरान वर्षा न हो, ऐसी भी कामना कर रहे हैं।

धर्मशाला में बरसात के कारण कई मैचों के धुल जाने के कारण, यहां मैच करवाने से ही पहले आयोजक भी मौसम का विचार जरूर करते हैं। हालांकि इस सबके बीच हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसासिएशन ने स्टेडियम को सजाने संवारने से लेकर पिच व मैदान को 20 मिनट में सुखाने सहित विशेष तरह के इंतजाम किए हैं। धर्मशाला स्टेडियम में एक दशक बाद हो रहे आईपीएल मैचों से क्रिकेट प्रेमियों और कारोबारियों को भी बड़ी उम्मीदें हैं। यही वजह है कि मैच के लिए टिकटों की साइट खुलते ही टिकटें सेल हो जाती हैं। बारिश के देवता इंद्रुनाग से भी मैच से पहले मौसम को लेकर हर बार प्रार्थना की जाती है। कई बार तो मौसम ने साथ ही दिया है। पर इस बार मई महीने में जिस तरह से मौसम बरसात और सर्द बना हुआ है, उसने क्रिकेट प्रेमियों ही नहीं, कांगड़ा घाटी के कारोबारियों की भी चिंता बढ़ा दी है।

हालांकि एचपीसीए ने यहां मौसम की मार को देखते हुए अब नई आउटफील्ड तैयार कर बारिश के पानी की निकासी के लिए एडवांस सब-एयर ड्रेनेज सिस्टम स्थापित कर दिया है। ऐसे में बारिश के बाद लगभग 20 मिनट में ही मैदान को सुखाया जा सकता है, जिससे हल्की या थोड़ी देर के लिए होने वाली बारिश का तो स्टेडियम पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।

लेकिन मई में जिस तरह से मौसम डरा रहा है, उससे सभी डर रहे हैं। इससे पहले वर्ष 2019 और 2020 में भी भारत और द. अफ्रीका के बीच दो मैच बारिश में धुल गए थे।

क्रिकेट प्रेमियों-कारोबारियों की भगवान इंद्रुनाग से अरदास

कांगड़ा घाटी के कारोबारी और क्रिकेट प्रेमी इस बार इंद्रुनाग देवता से मैच के समय मौसम सही रहने की कामना कर रहे हैं। जिससे मौसम की मार झेल रहे पर्यटन कारोबारियों को भी राहत मिल सके। होटल, टैक्सी, ट्रैकिंग से लेकर तमाम सारे लोग मौसम से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

दिल्ली की गुजरात टाइटंस पर शानदार जीत, कैपिटल्स ने पांच रन से जीत लिया मैच

अहमदागाद। इंडियन प्रीमियर लीग का 44वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स व गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया, जिसे दिल्ली ने पांच रन से जीत लिया। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में आठ विकेट के नुकसान पर 130 रन बनाए। फिर दिल्ली ने 131 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टीम को 20 ओवर में 125/6 रन पर रोक मुकाबला जीत लिया। इससे पहले गुजरात के अहमदाबाद स्टेडियम में दिल्ली की ओर अमन खान ने सबसे ज्यादा 51 रन बनाए। अक्षर पटेल ने 27 और रिपल पटेल ने 23 रन का योगदान दिया। वहीं गुजरात के लिए मोहम्मद शमी ने सर्वाधिक चार विकेट झटके। मोहित शर्मा को दो और राशिद खान को एक विकेट मिला। दिल्ली कैपिटल्स के लिए अमन खान ने 41 गेंदों पर फिफ्टी पूरी की।

अंतरराष्ट्रीय

संरा ने यूनिसेफ के दो उप कार्यकारी निदेशक किए नियुक्त

संयुक्त राष्ट्र (वार्ता)। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) के उप कार्यकारी निदेशक के रूप में सेवाएं देने के लिए दो नये सहायक महासचिव नियुक्त किये।

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, नीदरलैंड्स की किटी वैन डेर हेजडेन को साझेदारी के लिए उप कार्यकारी निदेशक तथा लेबनान के एडवर्ड चैबन को मानवीय कार्रवाई एवं आपूर्ति संचालन के लिए उप कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। दोनों वर्तमान उप कार्यकारी निदेशकों की जगह लेंगे। महासचिव और यूनिसेफ ने उनकी सेवाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। सुश्री किटी 2019 से अपने देश के विदेश मंत्रालय में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। उनके पास विश्व संसाधन संस्थान में अफ्रीका और यूरोप के उपाध्यक्ष एवं निदेशक के रूप में काम करने के साथ-साथ सतत विकास के लिए राजदूत तथा विदेश मंत्रालय में जलवायु, ऊर्जा, पर्यावरण एवं जल निदेशक के रूप में काम करने का भी अनुभव है। उन्होंने नीदरलैंड के इरास्मस विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल की है और उन्हें फ्रेंच के साथ डच और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान है।

चैबन ने यूनिसेफ में विभिन्न नेतृत्व पदों पर काम किया है, जिनमें मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रीय निदेशक, कार्यक्रमों के निदेशक, आपातकालीन कार्यक्रमों के निदेशक और इथियोपिया, सूडान तथा श्रीलंका में प्रतिनिधि शामिल हैं। उन्होंने हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन कंट्री-रेडीनेस एंड डिलीवरी के लिए यूनिसेफ के वैश्विक प्रमुख समन्वयक के रूप में काम किया है। उनके पास टफ्ट्स विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान और राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री तथा अमेरिका में जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय से विकास और अरब अध्ययन में मास्टर डिग्री है। उन्हें अंग्रेजी, फ्रेंच और अरबी भाषा का अच्छा ज्ञान है।

अमेरिका ने बनायी अफगान शरणार्थियों की अस्थायी नागरिकता को नवीनीकृत करने की योजना

वाशिंगटन, (वार्ता)। अमेरिका ने अफगानिस्तानी शरणार्थियों की अस्थायी नागरिकता को अगले दो साल के लिए नवीनीकृत करने की अनुमति देने की योजना बनाई है।

सीबीएस न्यूज ने एक रिपोर्ट में मंगलवार को यह जानकारी दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में करीब 77,000 अफगान शरणार्थियों को फिलहाल काम करने की इजाजत है। यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (यूएससीआईएस) जून में नवीनीकरण आवेदन स्वीकार करना शुरू कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में अमेरिका में लाए गए अफगान शरणार्थियों के पहले समूह की अस्थायी नागरिकता जुलाई में समाप्त होने वाली है। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2021 में,

अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में लौटने पर उसने तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी को इस्तीफा देने और देश छोड़ने के लिए कहा। अमेरिकी सेना भी अफगानिस्तान से लौट गयी। अफगानिस्तान भीषण आर्थिक संकट और भोजन की कमी के कारण मानवीय संकट की कगार पर पहुंच गया। अमेरिकी सेना ने उस समय अफगानिस्तान से 1,22,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला था।

शौकरी और ब्लिंकन ने सूडान की स्थिति पर चर्चा की

काहिरा (वार्ता)। मिस्र के विदेश मंत्री सामेह शौकरी ने अमेरिका के विदेश एंटनी ब्लिंकन के साथ सूडान की ताजा स्थिति पर चर्चा की है।

मिस्र के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने टेलीफोन पर बातचीत के दौरान सूडान में दीर्घकालिक एवं स्थायी संघर्ष विराम के प्रयासों पर बात की ताकि जरूरतमंदों तक मानवीय सहायता पहुंचायी जा सके।

श्री शौकरी ने संघर्ष विराम की स्थिरता सुनिश्चित करने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए बाहरी पक्षों के हस्तक्षेप से सूडान में संघर्ष को बढ़ावा नहीं देने के महत्व पर जोर दिया।

श्री ब्लिंकन ने हजारों सूडानी नागरिकों को अपने देश में आने की अनुमति देने के लिए मिस्र को धन्यवाद दिया तथा इस कार्य के लिए उसे आवश्यक सहायता देने की अमेरिका की तत्परता पर जोर दिया।

छोटी खबरें

बड़ूही में पेड़ से टकराई हरियाणा रोडवेज की बस, कंडक्टर सहित 2 की गई जान

ऊना। ऊना-अंब रोड पर बड़ूही बाजार में हरियाणा रोडवेज की बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कंडक्टर सहित दो लोगों की मौत हो गई। हादसा बुधवार सुबह 3:40 पर पेश आया। बस फरीदाबाद से बैजनाथ जा रही थी। हादसा इतना जबरदस्त था कि बस पेड़ से टकराने के बाद दूसरी तरफ एक मकान में जा घुसी, जिससे घर की दीवार गिरने से अंदर सो रहे परिवार को भी गंभीर चोटें लगीं। बस में बैठी पांच से सात सवारियों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं, जिन्हें एंबुलेंस के माध्यम से ऊना अस्पताल भेजा गया है। मौके पर जोल और अंब के पुलिसकर्मी भी पहुंच गए हैं और हादसे के कारणों की जांच कर रहे हैं।

सुंदरनगर में एनएच-21 पर जड़ोल के पास डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार, दो युवतियों को आई चोटें

सुंदरनगर। चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाई-वे पर हादसे कि थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा मामले में एनएच 21 पर जड़ोल में एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे दो युवतियों और चालक को मामूली चोटें आई हैं। राम चंद निवासी जड़ोल ने शिकायत दर्ज करवाई है कि जड़ोल फोरलेन पर सलापड़ की तरफ से एक कार तेज रफ्तार ने डिवाइडर में लगे कैमरा के पोल को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें दो युवतियों को चोटें आई हैं। हादसा कार चालक राजकुमार की लापरवाही से हुआ है। डीएसपी सुंदरनगर दिनेश कुमार ने मामले की पुष्टि की है।

रोहतांग में बर्फबारी; कुल्लू में भारी बारिश से तबाही, कई बस रूट प्रभावित, एनएच-305 बंद

कुल्लू। जिला कुल्लू में देर रात से झमाझम बारिश का दौर जारी है, वहीं रोहतांग दर्रा के साथ-साथ अटल टनल के आसपास भी बर्फबारी शुरू हो गई है। जिला कुल्लू की बात करें तो झमाझम बारिश होने से कई ग्रामीण मार्गों पर बस सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। इसके अलावा भारी बारिश होने से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है, वहीं एनएच 305 औट लुहरी मार्ग पर जलोड़ी के समीप भारी बारिश से एक पेड़ मार्ग पर गिर गया है, जिससे एनएच 305 वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है। पेड़ को हटाने में मशीनरी से कार्य हो रहा है।

वाइल्ड लाइफ एक्ट बदला, अब कोई जानवर वर्मिन नहीं, देश भर में लागू हुआ संशोधित एक्ट

शिमला। हिमाचल में बंदरों के बढ़ते खतरे के बाद उन्हें हिंसक जानवर (वर्मिन) की श्रेणी लाने पर बहस भले ही छिड़ गई हो, लेकिन अब किसी भी जानवर को वर्मिन श्रेणी में डालना संभव नहीं हो पाएगा। वाइल्ड लाइफ एक्ट में बदलाव हो चुका है। पिछले साल वाइल्ड लाइफ एक्ट को राज्यसभा से मंजूरी मिल गई थी। इस मंजूरी के साथ ही वाइल्ड लाइफ एक्ट में शामिल शेड्यूल-5 के प्रावधान को हटा दिया गया है। दरअसल शेड्यूल-5 में ही फसलों या मानव जीवन को खतरे में डालने वाले जानवरों को हिंसक घोषित करने का प्रावधान था। अब शेड्यूल को हटाने के बाद किसी भी जानवर को वर्मिन नहीं बनाया जा सकता है। गौरतलब है कि अधिनियम में बदलाव से पहले तक वर्मिन की श्रेणी में आने वाले जानवरों को कानूनी तौर पर मारने की इजाजत मिलती रही है। हिमाचल में बड़े पैमाने पर फसलों और आम लोगों को नुकसान पहुंचाने में बंदर सबसे आगे रहे हैं। इस क्रम को देखते हुए पूर्व में बंदरों को वर्मिन श्रेणी में लाने को लेकर प्रयास किए गए। हाल ही में शिमला में तीसरी मंजिल से गिरने के बाद यह युवती की मौत बंदरों की वजह से हुई है। इससे पहले 2014 में भी एक महिला की मौत बंदरों की वजह से हो चुकी है, जबकि बीते साल नवंबर महीने में बंदर 75 हजार रुपए से भरे बैग को लेकर रफूचक्कर हो गए थे। प्रदेश भर में बंदरों की उजाड़ से फसलें बर्बाद होने की शिकायतें भी अलग-अलग जिलों से सामने आती रही हैं। बंदरों के बढ़ते खौफ को देखते हुए प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी संज्ञान लिया है और तमाम विभागों से बंदरों को वर्मिन घोषित करने पर स्थिति साफ करने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन नए एक्ट के लागू होने के बाद अब बंदरों को वर्मिन घोषित नहीं किया जा सकता है, बल्कि उनकी आबादी को कम करने के लिए दूसरे रास्ते अपनाने होंगे।

बंदरों की नसबंदी पर जोर देंगे

वन विभाग के प्रमुख अरण्यपाल राजीव कुमार ने बताया कि बंदरों पर अंकुश लगाने के लिए विभाग नसबंदी को तेज करने जा रहा है। इसके अलावा लोगों को जागरूक किया जाएगा। रिहायशी इलाकों में बंदरों को खाने-पीने की चीजें मुहैया हो रही हैं और इस वजह से उनके झुंड घरों की छतों पर डटे रहते हैं। उन्होंने कहा कि कूड़े के ढेर भी बंदरों को आकर्षित करते हैं। इसके लिए संबंधित जिला प्रशासन और नगर निगम को भी ध्यान देने की जरूरत है।

मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल को फौरी राहत नहीं, छुट्टियों की वजह से हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

अहमदाबाद। 'मोदी सरनेम' मानहानि केस में राहुल गांधी की अपील पर गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। राहुल ने 2019 के मामले में खुद को दोषी ठहराए जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को इस मामले में कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस हेमंत प्रच्छक छुट्टियों के बाद इस मामले में फैसला सुनाएंगे। पांच मई को हाई कोर्ट का आखिरी वर्किंग डे है। इसके बाद गर्मी की छुट्टियों की वजह से कोर्ट अगले महीने पांच जून को खुलेगा। इसके बाद ही फैसला आ सकता है।

ऑपरेशन कावेरी: 5 नौसैनिक जहाजों, 13 विमानों का उपयोग करके 3,195 भारतीयों को निकाला

नई दिल्ली। भारत ने अब तक हिंसाग्रस्त सूडान से 3,195 भारतीयों को सुरक्षित निकाला है और उन्हें 60 से अधिक बसों में खार्तूम से सूडान बंदरगाह तक 850 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करके पहुंचाया है।

सूडान में भारतीय दूतावास ने ऑपरेशन कावेरी का अवलोकन करते हुए कहा कि ऑपरेशन में अब तक भारतीय नौसेना के पांच जहाजों और भारतीय वायु सेना के 13 विमानों का इस्तेमाल किया गया है। खार्तूम में चल रही लड़ाई के मद्देनजर दूतावास, जिसे आज अस्थायी रूप से सूडान के बंदरगाह पर स्थानांतरित कर दिया गया था, ने ट्वीट्स की एक श्रृंखला में यह जानकारी दी।

ऑपरेशन कावेरी का आठवां दिनः "खार्तूम और सूडान के अन्य हिस्सों में संघर्ष 15 अप्रैल 2023 को शुरू हुआ। भारत सरकार ने 'ऑपरेशन कावेरी' शुरू किया और सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारतीय नौसेना के जहाजों और भारतीय वायु सेना के विमानों को तेजी से तैनात किया।"

तिरंगे में लिपटे पति को देख बेहोश हो गई पत्नी

रिवालसर। पत्नी नेहा शहीद पति के पार्थिव शरीर से लिपट गई और रोते-बिखलाते बेहोश हो गई। माता- पिता, भाई-बहन ने शहीद की देह को अपनी बाहों से जकड़ लिया। जब शहीद की अंतिम यात्रा शुरू हुई, तो मां हीरा देवी और पत्नी ने रोते बिलखते संदीप की अर्थी को कंधा दिया। बूढ़े पिता हीरा लाल बेटे को इस तरह देख बेसुध से हो गए।

यह हृदय विदारक मंजर था मंडी जिला के रिवालसर का, जहां असम की दरांग फील्ड फायरिंग रेंज में हुई एक दुर्घटना में रिवालसर के सरध्वार गांव का संदीप कुमार शहीद हो गया। बुधवार को जैसे ही शहीद की देह पैतृक गांव पहुंची, पूरे गांव में चीखो-पुकार होने लगी। किसी के भी आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पूरा क्षेत्र शहीद संदीप कुमार अमर रहे के नारों से गूंजता रहा। उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हजूम उमड़ पड़ा। राजकीय सम्मान के साथ तिरंगें में लिपटे पार्थिव शरीर पर नजर पड़ते ही परिजनों की चीख पुकारों से सभी की आंखे नम हो गईं। बता दें कि संदीप कुमार असम में सोमवार को शहीद हो गए थे। तीस वर्षीय संदीप कुमार एक महीनें पहले ही छुट्टी काट कर वापस गए थे।

उत्तराखंड सरकार द्वारा कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

सुमित तिवारी / उत्तराखंड प्रहरी ब्यूरो

देहरादून। अन्य राज्यों की तुलना में उत्तराखण्ड राज्य में सिलिका सैण्ड की रायल्टी अधिक होने एवं इस कारण राज्य में सिलिका सैण्ड के व्यवसाय पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव के दृष्टिगत राज्य में सिलिका सैण्ड के व्यवसाय को सुदृढ एवं कारगर किये जाने के निमित्त अन्य राज्यों के अनुरूप रायल्टी दर व अपरिहार्य भाटक की वर्तमान प्रचलित दर को संशोधित किए जाने का निर्णय।

राज्य की सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल बाजपुर (पेराई क्षमता 4000 टी.सी.डी.) की आसवनी में शून्य उत्प्रवाह संयंत्र (जेड.एल.डी.) न होने के कारण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली तथा उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून के आदेशों के क्रम में बाजपुर चीनी मिल की आसवनी में दिनांक 23 जनवरी 2017 से एल्कोहॉल उत्पादन कार्य पूर्ण रूप से बन्द होने के फलस्वरूप बाजपुर चीनी मिल एवं आसवनी की वित्तीय स्थिति प्रतिकूलतः प्रभावित हो रही है। अतः राज्य की सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल बाजपुर की आसवनी को पुनः 25 के०एल०पी०डी० क्षमता पर संचालन के लिये आसवनी के आधुनिकीकरण करते हुए शून्य उत्प्रवाह संयंत्र (जेड.एल.डी.) लगाने, आसवनी में पूर्व स्थापित संयत्रों एवं कुछ अन्य संयत्रों के अनुरक्षण के लिये धनराशि बैंक से ऋण लिये जाने हेतु रू० 29.00 करोड़ की शासकीय प्रत्याभूति उपलब्ध कराये जाने का केबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया है।

राज्य में वित्त, लेखा सम्बन्धी एवं अन्य विषयों पर समस्त विभागों तथा सचिवालय स्तर के कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से वित्त विभाग के अधीन पं० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तराखण्ड देहरादून की स्थापना की गयी। साथ ही राज्य के अधिक से अधिक कार्मिकों के कौशल, प्रशासकीय प्रबन्धन एवं योग्यता क्षमता में वृद्धि करना, राज्य में विभिन्न वित्तीय नियमों, मैनुअलों एवं नियमावलियों में स्थापित नियमों की प्रास्थिति का परीक्षण, शोध एवं परिवर्तन की आवश्यकता पर राज्य सरकार को शोधात्मक परामर्श प्रदान करना, उक्त संस्थान का उद्देश्य है। संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विशेषज्ञ के रूप में मानव संसाधन का होना अपरिहार्य होने के दृष्टिगत संस्थान में सृजित पदों के अतिरिक्त पूर्णकालिक व्याख्याता/शोधकर्ता, Learning & Development Expert (Financial Management), Training Coordinator पदों का सृजन किए जाने का निर्णय लिया।

कोषागार विभाग के अन्तर्गत लेखा लिपिक का पद मृत संवर्ग घोषित होने के दृष्टिगत ऐसे नियमति एवं स्थायी अनुसेवक, जिन्होंने इण्टरमीडिएट (कॉमर्स) अथवा समकक्ष परीक्षा अथवा बी०कॉम परीक्षा उत्तीर्ण की हो, अनुसेवक के पद पर 10 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो तथा निर्धारित पाठ्क्रम के अनुसार अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, की पदोन्नति हेतु वर्तमान में सृजित कुल सहायक लेखाकार के 326 पदों के सापेक्ष जनपदवार कुल 17 पद आरक्षित किए जाने का निर्णय।

उत्तराखण्ड राज्य के चारधामों एवं श्री हेमकुण्ड साहिब की यात्रा हेतु प्रतिवर्ष लाखों की संख्या मे देशी एवं विदेशी तीर्थयात्री/पर्यटक आते है तथा प्रतिवर्ष यात्रियों की संख्या में निरन्तर हो रही वृद्धि के दृष्टिगत चार धाम यात्रा व्यवस्था को सुचारू रूप से संपन्न करने के उददेश्य से पूर्व से गठित यात्रा प्रशासन संगठन, ऋषिकेश का संगठनात्मक ढांचा अपर्याप्त होने के कारण उक्त संगठन का नाम परिवर्तित करते हुए चारधाम यात्रा प्रबन्धन एवं नियन्त्रण संगठन (Chardham Yatra Management and Control Organisation) किया गया है। उक्त संगठन के स्थाई कार्यालय हेतु 11 पदों के सृजन की स्वीकृति तथा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, पूछताछ केन्द्र सहायक / सहायक स्वागती, अनुसेवक कार्य हेतु 9 व्यक्तियों की सेवायें आउटसोर्स के माध्यम से लिये जाने का प्रावधान किया गया है। जिसे कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई।

पशुपालन विभाग के नियमित पशुचिकित्साविदों को फरवरी, 2014 से उन्हें अनुमन्य मूल वेतन (निर्धारित वेतन+ ग्रेड वेतन) के योग के 25 प्रतिशत की दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (NPA) दिया जा रहा था। केन्द्रीय सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिए गठित वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) द्वारा दिये गये प्रतिवेदन / संस्तुतियों में पशुपालन विभाग के चिकित्सकों को प्रैक्टिस बन्दी भत्ता के सम्बन्ध में कोई उल्लेख न होने के कारण पशुपालन विभाग के पशुचिकित्साधिकारियों को प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (NPA) दिया जाना रोक दिया गया था। पुनः प्रकरण वित्तीय नियम समिति को सन्दर्भित किया गया। वित्तीय नियम समिति द्वारा एलोपैथिक चिकित्सकों की भाँति राज्य पशुपालन विभाग के पशुचिकित्साविदों को 20 प्रतिशत प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (NPA) अनुमन्य किये जाने की संस्तुति की गयी है। जिसके क्रम में मा0 मंत्रिमण्डल द्वारा पशुपालन विभाग के चिकित्साविदों को 20 प्रतिशत प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (NPA) अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया है। इससे लगभग 400 पशुचिकित्साविद् लाभान्वित होंगे।

उत्तराखण्ड राज्य में वनाग्नि की घटनाओं हेतु चीड़ के वनों में पिरूल भी एक मुख्य कारण है । वनाग्नि सत्र 2023 में चीड़-पिरूल स्थानीय स्तर पर एकत्रीकरण करके व्यापक स्तर पर ब्रिकेट / पैलेट्स बनाये जाने की व्यवस्था विभाग स्तर से की जानी प्रस्तावित है। चीड़-पिरूल से घटित होने वाली वनाग्नि के रोकथाम हेतु एवं पिरूल एकत्रित करने के लिये क्षेत्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति विशेष द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था यथा-वन पंचायत, स्वयं सहायता समूह एवं युवक मंगल दल आदि के माध्यम से वन क्षेत्रों में पिरूल को एकत्रित कर स्थाई रूप से निष्कासित करने पर विभाग द्वारा उस व्यक्ति को संस्था के माध्यम से राज्य सैक्टर की संगत योजनाओं अथवा कैम्पा के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से रू0 2.00 प्रति किलोग्राम की दर से भुगतान किये जाने की स्वीकृति शासनादेश संख्या-2198 / X-2-2019-21 (9) 2015 दिनांक 05 नवम्बर, 2020 के द्वारा प्रदान की गयी थी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राज्य में चीड़-पिरूल एकत्रीकरण दर को आजीविका में वृद्धि के दृष्टिगत रू 2.00 प्रति किलोग्राम के स्थान पर रू0 3.00 प्रति किलोग्राम पुनरीक्षित किए जाने का निर्णय लिया गया।

उत्तराखण्ड राज्य में पशुधन हेतु वर्षभर हरे एवं सूखे चारे की उपलब्धता व पशुधन उत्पाद में वृद्धि के साथ महिलाओं के कार्यबोझ को कम करने के लिए उत्तराखण्ड चारा नीति प्रस्तावित की जा रही है। वर्तमान में आवश्यकता के सापेक्ष हरे चारे में 31 प्रतिशत तथा सूखे घारे में 17 प्रतिशत की कमी है। चारे की कमी की पूर्ति मुख्यत पंजाब एवं हरियाणा से आने वाले गेहूं के भूसे से की जाती है। भौगोलिक संरचना के कारण प्रदेश आपदा संभावित क्षेत्र है, जिसके कारण भी चारे की उपलब्धता बाधित होती रहती है। चारा नीति के क्रियान्वयन हेतु पशुपालन विभाग, सहकारिता विभाग, दुग्ध विकास विभाग तथा अन्य स्रोतों यथा REAP इत्यादि के समन्वय से कार्य सम्पादित किये जायेंगे तथा योजना में धनराशि की व्यवस्था राज्य अंश के अतिरिक्त भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य योजनाओं के माध्यम से की जायेगी। राज्य में हरे चारे की पर्याप्त उपलब्धता हेतु पशुपालकों को 13300 उन्नत किस्म के चारा बीज वितरण कर हरा चारा उत्पादन वृद्धि, वर्तमान साइलेज निर्माण क्षमता से 25 हजार मी० टन वृद्धि, पशुपालकों को चैफ कटर वितरण तथा सिल्वीपाश्चर को बढ़ावा दिया जाना प्रस्तावित है। प्रथम वर्ष में 53400 मी० टन सूखा चारा तथा 1125300 मी० टन हरा चारा मध्यावधि (01 से 03 वर्ष) में 20 हजार मी० टन सूखा चारा तथा 19 हजार मी० टन हरा चारा तथा दीर्घावधि (03 से 05 वर्ष) 01 लाख टन हरा चारा उत्पादन की वृद्धि होगी । उत्तराखण्ड चारा नीति, 2023-28 लागू होने पर चारे की कुल 31 प्रतिशत कमी में से 2352 प्रतिशत की कमी दूर हो जायेगी। वर्तमान मे राज्य सूखे चारे की उपलब्धता में वृद्धि के लिये एफ०पी०ओ० की स्थापना कर दुग्ध उत्पादक समिति के सदस्यों से अतिरिक्त 5 हजार मी०टन फसल अवशेष कय भूसे का सुगम परिवहन के लिये समीपवती भूसा आधिक्य राज्य हरियाणा अथवा पंजाब में सार्वजनिक, सहकारी तथा निजी क्षेत्र की सहायता से एक 20000 मी० टन की सघनीकृत भूसा इकाई की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। राज्य में भूसा भंडारण क्षमता में वृद्धि हेतु विभिन्न माध्यमों से 10 भूसा भंडारण गृह का निर्माण तथा राज्य में स्थापित चारा बैंकों में कॉम्पेक्ट फीड ब्लाक के अतिरिक्त साइलेज के भण्डारण क्षमता में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। कुल प्रस्तावित व्यय रू0 13655.00 लाख में से JICA-NPDD से रू 2367.00 लाख REAP से रू० 225500 लाख नाबार्ड मे रू 2000.00 लाखः तथा राज्य सैक्टर से रू 6683.60 लाख का व्यय उक्त योजनाओं के माध्यम से किया जायेगा।

राज्य सैक्टर में रू0 3110.00 लाख की

इन लोगों को गेहूं चावल के साथ साथ अब मंडुवे का आटा भी मिलेगा मुफ्त

उत्तराखंड प्रहरी ब्यूरो

देहरादून। सफेद और गुलाबी राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार अब इन राशन कार्ड धारकों को गेहूं चावल के साथ-साथ अब मुफ्त में मंडुवा भी देने जा रही हैं। सरकार मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सस्ते गल्ले की दुकानों में मंडुवा देने की योजना बनाई है। योजना के तहत सफेद और गुलाबी कार्ड धारकों को प्रत्येक माह 1 किलो मुफ्त में मंडुवा अनाज दिया जाएगा. योजना की शुरुआत मई माह से हो रही है।

क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक (RFC) कुमाऊं बीएस चलाल ने बताया कि मई से ही राशन कार्ड धारकों को मंडुवा दिया जाएगा। इसका आवंटन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि योजना की शुरुआत पहले चरण में नैनीताल और उधम सिंह नगर में की जानी है.उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ द्वारा इस बार जनवरी 2023 तक 1409 मीट्रिक टन मंडुवा की खरीद की गई। जहां राशन कार्ड धारकों को मई, जून, जुलाई माह तक 1 किलो प्रति राशन कार्ड मंडुवा उपलब्ध कराया जाना है। दोनों जिलों के लिए 3 माह के लिए 1068.7 मीट्रिक टन मंडुवा की डिमांड की गई है।

क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक (RFC) कुमाऊं बीएस चलाल ने बताया कि मई से ही राशन कार्ड धारकों को मंडुवा दिया जाएगा। इसका आवंटन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि योजना की शुरुआत पहले चरण में नैनीताल और उधम सिंह नगर में की जानी है। उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ द्वारा इस बार जनवरी 2023 तक 1409 मीट्रिक टन मंडुवा की खरीद की गई। जहां राशन कार्ड धारकों को मई, जून, जुलाई माह तक 1 किलो प्रति राशन कार्ड मंडुवा उपलब्ध कराया जाना है। दोनों जिलों के लिए 3 माह के लिए 1068.7 मीट्रिक टन मंडुवा की डिमांड की गई है। जहां मंडुवा उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है. योजना के तहत राज्य के करीब 13.91 लाख कार्ड धारक धारकों को

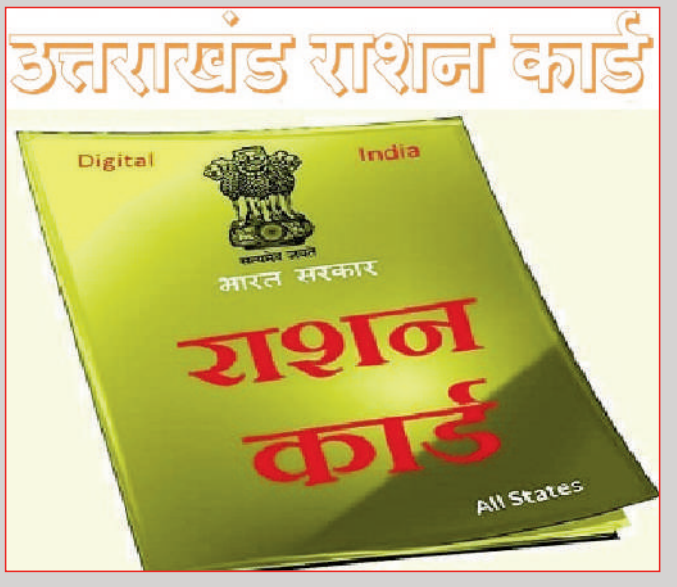

इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा है कि मोटे अनाज को प्रोत्साहित किया जाए. जिससे कि लोग अपनी पारंपरिक अनाज की ओर रुझान बढ़ सकें। जिससे किसान अधिक से अधिक मोटे अनाज का उत्पादन कर अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर सकें।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक/संपादक- विकास गर्ग ने भगवती प्रिंटिंग प्रेस, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार उत्तराखंड से मुद्रित करवाकर 54 आवास विकास, विवेक विहार, रानीपुर मोड़, हरिद्वार उत्तराखंड से प्रकाशित किया।
प्रकाशक / संपादक: विकास गर्ग- फोन : 9897766448, : मुख्य संपादक / सुमित तिवारी- फोन : 8077771906: Email : uttarakhandprahari19@Gmail.com